International Journal of Applied Research 2016; 2(11): 481-485

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(11): 481-485
www.allresearchjournal.com
Received: 27-09-2016
Accepted: 29-10-2016

डॉ0 डिगर सिंह फर्स्वाण
विभागाध्यक्ष (बी.एड), देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, लालपुर रूद्रपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत।

बबीता रानी वासन
सहायक प्राध्यापक (बी.एड), देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, लालपुर रूद्रपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत।

Correspondence
डॉ0 डिगर सिंह फर्स्वाण
विभागाध्यक्ष (बी.एड), देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, लालपुर रूद्रपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत।

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवाह आरेखण का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

डॉ0 डिगर सिंह फर्स्वाण और बबीता रानी वासन

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन में जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवाह आरेखण का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कुल विद्यार्थियों का अध्ययन हेतु चयन किया गया है। विद्यालयों में प्रवाह आरेखण का अर्थ बालक–बालिका का अनुत्तीर्ण होने या अन्य कारणों से एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक अध्ययन करने से होता है। जिस कारण बालक–बालिकाएं निर्धारित समय में प्राथमिक शिक्षा चक्र को पार नही कर पाते है। जिससे शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्याओं में वृद्धि होने लगती है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवाह आरेखण में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण को दृष्टिगत् रखते हुए सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा निरन्तर बुनियादी तथा प्राथमिक शिक्षा तक सबकी पहुँच तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने की पहल की जा रही है जिससे बच्चों के भविष्य का ठोस आधार विकसित हो सके। परन्तु कई कारणों से जैसे माता–पिता की निरक्षरता, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, विषम भौगोलिक परिस्थितियॉ तथा समुचित व्यवस्थाओं का अभाव होने से आज भी बुनियादी शिक्षा में प्रवाह आरेखण जैसी समस्यायें व्याप्त है जिनके समाधान किये बिना गुणवत्तापरक बुनियादी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र तथा समाज के भविष्य का ठोस आधार विकसित करना संभव नहीं है।

मूल शब्द: प्रवाह आरेखण, सार्वभौमीकरण, अपव्यय एवं अवरोधन, प्राथमिक शिक्षा चक्र, गुणवत्तायुक्त।

प्रस्तावना
शिक्षा का मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में परोक्ष तथा अपरोक्ष रुप से गहन सम्बन्ध होता है। व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष शारीरिक, मानसिक, भौतिक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यवसायिक, राजनैतिक तथा सामाजिक आदि शिक्षा से जुड़े रहते है। इससे वे प्रभावित होते है तथा इसे प्रभावित करते है। प्राथमिक शिक्षा का मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के आधार पर ही बालक के भविष्य की दिशा निर्धारित होती है। जन्म के समय बालक निर्बल एवं असहाय होता है, परन्तु उसमें अनेक प्रकार की शक्तियॉ विद्यमान होती है। शिक्षा द्वारा इन शक्तियों का विकास किया जाता है। विकास शून्य में नहीं होता है इसके लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। सभी शक्तियों का विकास अलग–अलग नहीं होता। वातावरण में विकसित होने वाले तत्व साथ–साथ करते है। जैसे मस्तिष्क के साथ–साथ पेशियॉ भी कार्यरत रहती है। शरीर विकसित होता है तो साथ ही साथ मानसिक विकास भी होता है। सभी पक्षों एवं अंगो का विकास एक तालमेल के साथ किया जाना आवश्यक है ताकि ये शक्तियॉ एक दूसरे से सुसम्बद्ध होकर पुष्ट एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के रुप में प्रकट हो सकें। इसमें शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षा एक ऐसी प्रकिया है जो बालक तथा मनुष्य के अन्दर छिपी हुई शक्तियों का सर्वोमुखी विकास करती है। यह विकास किस प्रकार का हो, इसकी रुपरेखा भी गॉधी जी ने बतलाई है। यह विकास शरीर का है, मन का है तथा आत्मा का है। विकास किस प्रकार का हो सकता है तथा किस प्रकार से किया ता सकता है, इनका उत्तर है–यह विकास एक विशेष प्रकार के वातावरण में हो सकता है। स्कूल द्वारा यह वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षा इस प्रकार से प्रयत्न करता है कि बालक को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जो उसकी आन्तरिक शक्तियों का इस प्रकार विकास करने में सहायक हो जिससे बालक समाज का उपयोगी सदस्य बन सके। शिक्षा के अर्थ की व्याख्या करते हुए गॉधी जी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अर्थ अक्षर–ज्ञान नहीं है। शिक्षा एक साधन मात्र है। हम मनुष्य बनें। मात्र पुस्तकीय ज्ञान से

मनुष्यत्व नहीं आता। ज्ञान के साथ–साथ शरीर तथा आत्मा का विकास भी अत्यन्त आवश्यक है। सर्वांगीण शिक्षा का विकास इस प्रकार से हो कि बालक में विद्यमान शक्तियों को ऐसा मोड़ दिया जाए कि वह एक आदर्श नागरिक बन सके। आदर्श नागरिक वही होगा जो जीविका उपार्जन भी कर सके। इसके लिए गॉधी जी ने दस्तकारी की शिक्षा पर बल दिया। सर्वांगीण विकास में संगीत तथा कला का विकास भी आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार के गुणों का बीज जन्मजात होता है। उसे बाहर निकालने के अवसर मिलने चाहिए। शुद्ध आचरण तथा नैतिक शिक्षा आदि सर्वांगीण शिक्षा के अभिन्न अंग है। गॉधी जी का मत है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा हाथ, पैर, ऑख, कान, नाक आदि शरीर के अंगो के ठीक अभ्यास और शिक्षण से हो सकती है। दूसरें शब्दों में, इन्द्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि को विकास का उतम और लद्युतम मार्ग मिलता है, परन्तु जब तक मस्तिष्क और शरीर का विकास साथ –साथ न हो और उसी मात्रा में आत्मा की जागृति न होती रहे, तब तक केवल बुद्धि के एकांकी विकास से कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। अतः शरीर, मन और आत्मा की विविध शक्तियों के विकास में उचित तालमेल और एकरसता लाने की अत्यन्त आवश्कता है।

आज किसी भी देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क है। अनिवार्य का अर्थ है कि कम से कम इतनी शिक्षा तो सभी को प्राप्त करनी चाहिए। जो शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होती है उसे ही सामान्य रुप से जन शिक्षा कहते है। हमारे देश में 1937 में प्रान्तों में स्वायत्त शासन स्थापित हुआ। उसी वर्ष गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की जिससें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव किया। गॉधी जी एवं उनके साथियों ने इसके लिए मातृभाषा एवं हस्तकौशल प्रधान पाठ्यचर्या तैयार की और इसका सम्बन्ध जीवन से जोड़ा। स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 1960–61 के बाद प्राथमिक शिक्षा में काफी तेजी आई और उसमें लगभग 3 करोड़ बच्चे प्रति दशक बढ़ते गये। परन्तु चौकाने वाली बात यह है कि 2004–05 में भी 6–14 आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं से बाहर थे। इनमें से लगभग 3 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिन्होनें प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ दी थी और लगभग 2 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिन्होनें प्राथमिक स्कूलों में नामांकन ही नहीं कराया था। वर्ष 2008 तक कक्षा 1 से 8 तक अपव्यय लगभग 45 प्रतिशत और अवरोधन लगभग 40 प्रतिशत था। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है फिर भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी विकास करना शेष है और इसके साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा का और प्रसार व उन्न्यन करना शेष है। प्राथमिक शिक्षा देश के प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य की नींव होती है। जब तक प्राथमिक शिक्षा रुपी यह नींव मजबूत नहीं होगी तब तक व्यक्ति के सर्वांगींण विकास तथा राष्ट्र के चहुॅमुखी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा संचालित किसी भी स्तर की शिक्षा समान होनी चाहिए। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ प्रत्येक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने में जन सहयोग आवश्यक है। परन्तु यह सब नियम एवं कानून बनाने से तथा आंकड़ेवाजी से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जनचेतना एवं जनजागरुकता जागृत करना आवश्यक है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के चार पहलू है जिसमें प्रथम शत–प्रतिशत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना द्वितीय शत–प्रतिशत बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराना तीसरा शत–प्रतिशत बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में रोके रखना और चौथा शत–प्रतिशत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हुए प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण कराना। और ये चारों अपने में समस्यायें है। जब तक इन समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक पहल तथा जबावदेही सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक इन समस्याओं का शत–प्रतिशत समाधान संभव नहीं है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी प्रकार के प्राथमिक विद्यालयों को प्रान्तीय सरकारों के प्रशासनिक ढ़ॉचे के अर्न्तगत लाना, अति मंहगी संस्थाओं पर नियंत्रण करना, साधन विहीन संस्थाओं की दशा सुधारना, जनजागरुकता का प्रसार करना तथा सभी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। रैकवार, (2000) के अनुसार शिक्षा में गुणवत्ता का अर्थ है मानक स्तर की शिक्षा विद्यार्थी अपनी आयु एवं कक्षा के अनुसार शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करें यह समाज की मॉग होती है। शिक्षा मनुष्य के विकास की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धारा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में ''सभी के लिए शिक्षा'' की पुनरावृत्ति की गयी थी। इसमें जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र तथा गरीबी–अमीरी के भेदभाव के बिना सभी बच्चों को क्षमता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में यह उल्लेख किया गया है कि देश में संचालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का सघन मूल्यांकन आवश्यक है जिससे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति एवं गुणवत्ता का आंकलन किया जा सकता है। प्रारम्भिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन एक भीषण समस्या है। इस समस्या के प्रति 1929 में हर्टांग समिति ने ध्यान आकृष्ट किया था। समिति ने कहा कि यद्यपि प्राथमिक विद्यालयों तथा बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा में प्रगति हो रही है आज भी कितने ही अभिभावक ऐसे हैं जो कठिन परिस्थितियों के शिकंजे में फंसे होने के कारण अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालयों से पृथक कर लेते हैं। गुप्ता (1983), तोमर (1991) तथा मिश्र (1998) के अनुसार भारत में औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा का भी महत्व कम नही रहा है क्योंकि इसके माध्यम से 6 से 14 आयु वर्ग के शालात्यागी तथा कतिपय कारणों से निरक्षर रह गये बालक–बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है

नयाल (1985) ने शिक्षा में पलायन की समस्या का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया कि हाईस्कूल स्तर पर पलायनवादी व्यवहार के लिए विभिन्न सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारक संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। हमारी अनाकर्षक शिक्षा व्यवस्था भी हाईस्कूल स्तर पर पलायन के लिए जिम्मेदार थी।

वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा में प्रवाह आरेखण एक ज्वलन्त समस्या है। प्रवाह आरेखण के अन्तर्गत नामांकन, प्रवेश, कक्षा प्रोन्नत, कक्षा पुनरावृत्ति तथा कक्षा शालात्यागी जैसी समस्यायें आती हैं। ये समस्यायें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालयों मे नामांकित कराकर उन्हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जाती तथा प्राथमिक विद्यालयों में किन्हीं कारणों से बार–बार कक्षा पुनरावृत्ति एवं विद्यालय पलायन जैसी समस्याओ का निदान नहीं किया जायेगा तब तक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन होगा। हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा में 'अवरोधन' की समस्या भी उतना ही विकराल है जितना कि अपव्यय। अवरोधन की समस्या प्राथमिक शिक्षा में प्रारम्भ से ही एक गम्भीर चुनौती था।

पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की

रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से रैकवार (2000), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), नयाल (1985), कोठारी कमीशन (1964–1966), डी0पी0ई0पी0 प्प् (2006), गुप्ता (1983), तोमर (1991), मिश्र (1998) एवं वर्धा शिक्षा योजना (1937) ने शोध विषय से सम्बन्धित कार्य किये है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किया गया हैः–

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवाह आरेखण का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

शोध कार्य की मुख्य परिकल्पना निम्न हैः–

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवाह आरेखण में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

विधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–1 से 5 तक के सभी बच्चों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

उपकरण तथा तकनीकें

प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श समूहों के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर 't' मान की सहायता से मध्यमान अन्तर की सार्थकता का आंकलन किया गया है।

't' परीक्षण के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया

$$t = \frac{M1-M2}{SED}$$

M_1= पहले न्यादर्श समूह का मध्यमान

M_2= दूसरे न्यादर्श समूह का मध्यमान

SED = मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि

$$SED = \sqrt{PQ\left[\frac{1}{N1} + \frac{1}{N2}\right]}$$

$$P = \frac{N1P1+N2P2}{N1+P1}$$

$$\text{आगत–निर्गत अनुपात} = \frac{\text{व्यय विद्यार्थी वर्ष (वास्तविक)}}{\text{आदर्श विद्यार्थी वर्ष}}$$

प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका संख्या–01 में विकासखण्ड गंगोलीहाट का कुल बच्चों का कोहोर्ट दर्शाया गया है। इस कोहोर्ट में प्राथमिक शिक्षा चक्र की प्रथम कक्षा में 2233 विद्यार्थी नामांकित थे। जिनमें से कक्षा 1 में 54 विद्यार्थियों द्वारा शालात्याग किया गया, 258 विद्यार्थियों ने कक्षा रिपीट की तथा 1921 विद्यार्थियों ने कक्षा प्रोन्नत किया। कक्षा 1 में रिपीटेड 258 विद्यार्थियों में से 128 प्रोन्नत हुए, 39 शालात्यागी हुए तथा 91 विद्यार्थी पुनः रिपीट कर गये। कक्षा 2 में आये प्रोन्नत 1921 बच्चों में से 1890 बच्चे प्रोन्नत हुए, 10 ने शालात्याग किया तथा 21 बच्चों ने कक्षा रिपीट किया।

5 वर्ष बाद इस शिक्षा की अन्तिम कक्षा में 1521 विद्यार्थी पहुंचे जिनमें से कुल 1430 विद्यार्थी प्राइमरी ग्रेजुएट हुए।

6 वर्ष बाद कक्षा 5 में 322 विद्यार्थी पहुंचे जिनमें से 265 विद्यार्थी जो 6 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट हुए।

7 वर्ष बाद कक्षा 5 में 142 विद्यार्थी पहुंचे जिनमें से कुल 130 विद्यार्थी पूरे कोहोर्ट में 7 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट हुए।

इस प्रकार वर्ष 2008–09 तक 2002–03 वर्ष के 2233 विद्यार्थियों में से 1430 + 265 + 130 = 1825 बच्चों ने शिक्षा चक्र पूरा किया तथा शेष 408 विद्यार्थियों के द्वारा शालात्याग किया गया।

पुनरावृत्ति के कारण अपव्यय=

= 1825 प्राइमरी ग्रेजुएट होने में 1430 बच्चों को लगे 5 वर्ष (जो उचित हैं)

= 265 बच्चों को प्राइमरी ग्रेजुएट होने में लगे 6 वर्ष (1 वर्ष अधिक)

= 130 बच्चों को प्राइमरी ग्रेजुएट होने में लगे 7 वर्ष (2 वर्ष अधिक)

अतः पुनरावृत्ति के कारण अपव्यय

= 265 × 1 + 130 × 2

= 265 + 260

= 525 विद्यार्थी वर्ष

शालात्यागी के कारण अपव्यय

= 54 × 1 + 49 × 2 + 91 × 3 + 86 × 4 + 74 × 5 + 42 × 6 +12 × 7

= 54 + 98 + 273 + 344 + 370 + 252 + 84

= 1475 विद्यार्थी वर्ष

कुल अपव्यय

= पुनरावृत्ति के कारण अपव्यय + शालात्यागी के कारण अपव्यय

= 525 + 1475 = 2000 विद्यार्थी वर्ष

अतः कुल 2233 विद्यार्थियों में से 1825 विद्यार्थियों को शिक्षा चक्र पार करने में 9125 विद्यार्थी वर्ष लगने चाहिए थे परन्तु 11125 विद्यार्थी वर्ष लगे जो कि 2000 विद्यार्थी वर्ष अधिक थे।

तालिका 1: प्रवाह आरेखण – गंगोलीहाट (कुल बच्चे)

कक्षा 1 में कुल नामांकित बच्चे	5 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट	6 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट	7 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट	कुल अपव्यय विद्यार्थी वर्ष
2233	1430	265	130	2000

तालिका संख्या–02 में विकासखण्ड गंगोलीहाट का बालकों का कोहोर्ट दर्शाया गया है। इस कोहोर्ट में प्राथमिक शिक्षा चक्र की प्रथम कक्षा में 1026 बालक नामांकित थे। जिनमें से कक्षा 1 में 24 बालकों द्वारा शालात्याग किया गया, 98 बालकों ने कक्षा रिपीट की तथा 904 बालकों ने कक्षा प्रोन्नत किया। कक्षा 1 में रिपीटेड 98 बालकों में से 39 प्रोन्नत हुए, 18 शालात्यागी हुए तथा 41 बालक पुनः रिपीट कर गये। कक्षा 2 में आये प्रोन्नत 904 बालकों में से 880 बालक प्रोन्नत हुए, 08 ने शालात्याग किया तथा 16 बालकों ने कक्षा रिपीट किया।

5 वर्ष बाद इस शिक्षा की अन्तिम कक्षा में 712 बालक पहुंचे जिनमें से कुल 670 बालक प्राइमरी ग्रेजुएट हुए।

6 वर्ष बाद कक्षा 5 में 135 बालक पहुंचे जिनमें से 110 बालक जो 6 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट हुए।
7 वर्ष बाद कक्षा 5 में 65 बालक पहुंचे जिनमें से कुल 60 बालक पूरे कोहोर्ट में 7 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट हुए।
इस प्रकार वर्ष 2008–09 तक 2002–03 वर्ष के 1026 बालकों में से 670 + 110 + 60 = 840 बालकों ने शिक्षा चक्र पार किया तथा 186 बालकों द्वारा शालात्याग किया गया।

पुनरावृत्ति के कारण अपव्यय =
= 840 प्राइमरी ग्रेजुएट होने में 670 बालको को लगे 5 वर्ष (जो उचित हैं)
= 110 बालकों को प्राइमरी ग्रेजुएट होने में लगे 6 वर्ष (1 वर्ष अधिक)
= 60 बालकों को प्राइमरी ग्रेजुएट होने में लगे 7 वर्ष (2 वर्ष अधिक)

अतः पुनरावृत्ति के कारण अपव्यय
= 110 × 1 + 60 × 2
= 110 + 120
= 230 विद्यार्थी वर्ष

शालात्यागी के कारण अपव्यय
= 24 × 1 + 26 × 2 + 44 × 3 + 33 × 4 + 35 × 5 + 19 × 6 + 5 × 7
= 24 + 52 + 132 + 132 + 175 + 114
= 664 विद्यार्थी वर्ष।

कुल अपव्यय
= पुनरावृत्ति के कारण अपव्यय + शालात्यागी के कारण अपव्यय
= 230 + 664
= 894 विद्यार्थी वर्ष।

अतः कुल 1026 बालकों में से 840 बालकों को शिक्षा चक्र पार करने में 4200 विद्यार्थी वर्ष लगने चाहिए थे परन्तु 5094 विद्यार्थी वर्ष लगे जो कि 894 विद्यार्थी वर्ष अधिक थे।

तालिका 2: प्रवाह आरेखण – कुल बालक

कक्षा 1 में कुल नामांकित बालक	5 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट	6 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट	7 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट	कुल अपव्यय विद्यार्थी वर्ष
1026	670	110	60	894

तालिका संख्या–03 में विकासखण्ड गंगोलीहाट का बालिकाओं का कोहोर्ट दर्शाया गया है। इस कोहोर्ट में प्राथमिक शिक्षा चक्र की प्रथम कक्षा में 1207 बालिकाए नामांकित थे। जिनमें से कक्षा 1 में 30 बालिकाओं द्वारा शालात्याग किया गया, 160 बालिकाओं ने कक्षा रिपीट की तथा 1070 बालिकाओं ने कक्षा प्रोन्नत किया। कक्षा 1 में रिपीटेड 160 बालिकाओं में से 89 प्रोन्नत हुए, 21 शालात्यागी हुए तथा 50 बालिकाए पुनः रिपीट कर गये। कक्षा 2 में आये प्रोन्नत 1017 बालिकाओं में से 1010 बालिकाए प्रोन्नत हुए, 02 ने शालात्याग किया तथा 05 बालिकाओं ने कक्षा रिपीट किया।
5 वर्ष बाद इस शिक्षा की अन्तिम कक्षा में 809 बालिकाए पहुंचे जिनमें से कुल 760 बालिकाए प्राइमरी ग्रेजुएट हुए।
6 वर्ष बाद कक्षा 5 में 187 बालिकाए पहुंचे जिनमें से 155 बालिकाए जो 6 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट हुए।
7 वर्ष बाद कक्षा 5 में 77 बालिकाए पहुंचे जिनमें से कुल 70 बालिकाए पूरे कोहोर्ट में 7 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट हुए।
इस प्रकार वर्ष 2008–09 तक 2002–03 वर्ष के 1207 बालिकाओं में से 760 + 155 + 70 = 985 बालिकाओं ने शिक्षा चक्र पूरा किया तथा 222 बालिकाओं द्वारा शालात्याग किया गया।

पुनरावृत्ति के कारण अपव्यय
= 985 प्राइमरी ग्रेजुएट होने में 760 बालिकाओं को लगे 5 वर्ष (जो उचित हैं)
= 155 बालिकाओं को प्राइमरी ग्रेजुएट होने में लगे 6 वर्ष (1 वर्ष अधिक)
= 70 बालिकाओं को प्राइमरी ग्रेजुएट होने में लगे 7 वर्ष (2 वर्ष अधिक)

अतः पुनरावृत्ति के कारण अपव्यय
= 155 × 1 + 70 × 2
= 155 + 140
= 295 विद्यार्थी वर्ष

शालात्यागी के कारण अपव्यय
= 30 × 1 + 23 × 2 + 47 × 3 + 53 × 4 + 39 × 5 + 23 × 6 + 7 × 7
= 30 + 46 + 141 + 212 + 195 + 138 + 49
= 811 विद्यार्थी वर्ष

कुल अपव्यय = पुनरावृत्ति के कारण अपव्यय + शालात्यागी के कारण अपव्यय = 295 + 811 = 1106 विद्यार्थी वर्ष
अतः कुल 1207 बालिकाओं में से 985 बालिकाओं को शिक्षा चक्र पार करने में 4925 विद्यार्थी वर्ष लगने चाहिए थे परन्तु 6031 विद्यार्थी वर्ष लगे जो कि 1106 विद्यार्थी वर्ष अधिक थे।

तालिका 03: प्रवाह आरेखण – कुल बालिकाए

कक्षा 1 में कुल नामांकित बालक	5 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट	6 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट	7 वर्ष बाद प्राइमरी ग्रेजुएट	कुल अपव्यय विद्यार्थी वर्ष
1207	760	155	70	1106

परिणाम

कक्षा 1 में कुल नामांकित बच्चों को शिक्षा चक्र पार करने में 9125 विद्यार्थी वर्ष की अपेक्षा 11125 विद्यार्थी वर्ष लगे जो कि 2000 विद्यार्थी वर्ष अधिक थे।
कक्षा 1 में कुल नामांकित बालकों को शिक्षा चक्र पार करने में 4200 विद्यार्थी वर्ष की अपेक्षा 5094 विद्यार्थी वर्ष लगे जो कि 894 विद्यार्थी वर्ष अधिक थे।
कक्षा 1 में कुल नामांकित बालिकाओं को शिक्षा चक्र पार करने में 4925 विद्यार्थी वर्ष की अपेक्षा 6031 विद्यार्थी वर्ष लगे जो कि 1106 विद्यार्थी वर्ष अधिक थे।

निष्कर्ष

उपर्युक्त शोध अध्ययन के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवाह आरेखण में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया

गया। दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था परन्तु यह अन्तर सांख्यकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक बालिकायें लगभग समान रूप से प्रवाह आरेखण की समस्या से प्रभावित थे। अतः परिकल्पना सही सिद्ध होती है।

अध्ययन के निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रवाह आरेखण के अध्ययन के उपरान्त निम्नलिखित सुझाव समीचीन प्रतीत होते है। ये निष्कर्ष एंव सुझाव शिक्षा के योजनाकारों, प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते है।

1. प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवाह आरेखण के कारणों को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण सृजित किया जा सकता है जिससे बच्चे उच्च शैक्षिक उपलिब्ध स्तर को प्राप्त कर सकते है।
2. बुनियादी शिक्षा में एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष व्यतीत करने के कारणों को पता लगाकर उसके समाधान हेतु ठोस नीति तैयार किया जा सकता है।
3. प्राथमिक शिक्षा में कक्षा पुनरावृत्ति की समस्या के समाधान के लिए शिक्षण नवाचारों का प्रयोग कर शिक्षण को व्यावहारिक, आसान व रूचिकर बनाने का प्रयास अपेक्षित है।
4. जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे है अथवा निम्न शैक्षिक उपलिब्ध के कारण अवसादग्रस्त है उनके मार्गदर्शन हेतु परामर्शदाता की व्यवस्था विद्यालयों में की जानी चाहिए।
5. प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एंव अवरोधन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए इस हेतु माता–पिता तथा अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए निरन्तर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।
6. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के साथ–साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापो में बच्चो की समुचित भागेदारी सुनिश्चित कराकर तथा शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग किया जाये, जिससे बच्चों में शिक्षण के प्रति रूचि तथा आत्मविश्वास में वृद्धि किया जा सके।
7. प्राथमिक शिक्षा हेतु दूरस्थ क्षेत्रों में समस्त शैक्षिक सुविधायें विकसित कर नामांकन और ठहराव में वृद्धि किया जा सकता है।
8. प्राथमिक विद्यालयों में बार–बार अनुतीर्ण होने, धनाभाव तथा अन्य कारणों से विद्यालय पलायन के कारणों को पता लगाकर उसके समाधान हेतु ठोस नीति तैयार किया जा सकता है।

स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में प्रवाह आरेखण होने से अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्यायें व्याप्त होती हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा में प्रवाह आरेखण के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का सार्थक प्रयास नहीं किया जायेगा तब तक राष्ट्र तथा समाज के भविष्य का ठोस आधार विकसित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रयास किया जाना समीचीन होगा क्योंकि राष्ट्र का भविष्य इन्हीं बालक व बालिकाओं के कन्धों पर है। जब तक सभी बालक–बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कराकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगींण विकास नहीं किया जाता तब तक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना व्यर्थ ही होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रैकवार, रामगोपाल (2000) प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता स्तर की समस्या, प्राइमरी शिक्षक, अप्रैल, 12–16।
2. गुप्ता, दलजीत (1983) ''ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ नॉनफारमल एजुकेशन प्रोग्राम'' (ऐज ग्रुप 9–14) रन बाई डिफेन्ट एजेन्सीज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पी0एच0डी0 एजुकेशन, भोपाल विश्वविद्यालय ।
3. मिश्र, जयनारायण (1998) अनुदेशकों की दृष्टि में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की समस्यायें, भारतीय आधुनिक शिक्षा, जुलाय, 15–23।
4. तोमर, लज्जाराम (1991) भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, सुरूचि प्रकाशन केशवकुंज झण्डेवाला, नई दिल्ली, संस्करण।
5. गैरेट, एच. ई (1981) मनोविज्ञान एंव शिक्षा में सांख्यिकी। दशम संस्करण। बी एफ एण्ड सन्स बॉम्बे।
6. नयाल, जी. एस (1985) विद्यालय से पलायन के कारण भारतीय आधुनिक शिक्षा। वर्ष द्वितीय अंक चतुर्थ। एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली।
7. उतरांचल दूरस्थ शिक्षा कार्यकम (2006) विद्यार्थी प्रवाह आरेखण एंव विश्लेषण। उतरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद डी. पी. ई. पी. – 3 देहरादून।
8. पाठक, पी. डी एंव त्यागी, जी. एस. डी. (2008) भारतीय शिक्षा के आयोग कोठारी कमीशन सहित। आगरा पब्लिकेशन आगरा।
9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2002) सर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक अभियान। नई दिल्ली : प्रारम्भिक शिक्षा एंव साक्षरता विभाग।